शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 28 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 7 – 14 जुलाई 2025 मूल्य पांच रूपये

निगम के प्रस्ताव के बिना ही मंत्रिमंडल द्वारा फैसला ले लेना आया सवालों में

- आर.एस.बाली का खुलासा भारी पड़ सकता है सरकार पर
- लाभ कमा रही ईकाई की संपत्ति प्राइवेट सैक्टर को देना कितना सही ?
- क्या सरकार रूल्स ऑफ बिजनेस को भी अनदेखा कर रही है?

शिमला/शैल। क्या सुक्खू सरकार विधानसभा द्वारा पारित कार्य निष्पादन नियमों की भी अनदेखी करने लग गयी है। यह सवाल पर्यटन विकास निगम के चौदह होटलों को ओ एन एम आधार पर निजी क्षेत्र को सौंपने के प्रस्तावित फैसले पर निगम के ही अध्यक्ष द्वारा एक पत्रकार वार्ता में एतराज उठाये जाने के बाद चर्चा में आया है। पर्यटन निगम अध्यक्ष विधायक आर.एस.बाली ने पत्रकार वार्ता में स्पष्ट कहा है कि निगम की ओर से इस आश्य का कोई प्रस्ताव सरकार को न ही भेजा गया और न ही निदेशक मण्डल द्वारा कभी पारित किया गया। बाली ने यह भी स्पष्ट कहा कि शायद सरकार और मंत्रिमंडल के सामने सारे तथ्य रखे ही नहीं गये हैं। इस समय पर्यटन निगम लाभ कमा रही है और टर्नओवर अढ़ाई वर्ष में 70 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ से ऊपर हो गया है। फिर बीते अढ़ाई वर्षो में पर्यटन निगम को सरकार की ओर से कोई ग्रांट नहीं मिली है। जबकि इसकी मांग कई बार की गयी। ऐसे में स्पष्ट है कि पर्यटन निगम की कार्यशैली में काफी सुधार हुआ है और उसके कर्मचारी निगम को लाभ की इकाई में बदलने में सफल हो गये हैं। इसलिये जो ईकाई लाभ कमाने में आ गई हो उसकी संपत्तियों को प्राइवेट सैक्टर को सौंपने का कोई औचित्य नहीं बनता। फिर जो चौदह इकाइयां प्राईवेट सैक्टर को सौंपने का फैसला लिया गया उनके रैनोवेशन के लिये निगम को ही धन उपलब्ध करवाया जाना चाहिये क्योंकि वह बनी हुई इकाइयां है और शीघ्र ऑपरेटिव हो जायेंगी। इनके रखरखाव के लिए एशियन विकास बैंक द्वारा दिये जा रहे कर्ज में से पैसा उपलब्ध करवाया जा सकता है। इस परिदृश्य में सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिये।

आर.एस.बाली मुख्यमंत्री के विश्वास पात्रों में गिने जाते हैं। ऐसे में बाली द्वारा यह सार्वजनिक करना कि निगम के प्रस्ताव के बिना ही इस तरह का फैसला ले लिया जाना अपने में कई सवाल खड़े कर जाता है। क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस के अनुसार किसी भी कार्य का कोई भी प्रस्ताव निगम बोर्ड विभाग द्वारा सरकार में सचिव को भेजा जाता है। उस प्रस्ताव पर सचिव और विभाग के मंत्री में मंत्रणा होती है। यदि सचिव और मंत्री की राय में मतभेद हो तब उस विषय को मंत्रिपरिषद में ले जाया जाता है। यदि

मंत्री और सचिव दोनों सहमत हो तो विषय को आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि मंत्री अपने में सक्षम होता है। पर्यटन निगम के चौदह होटल को प्राइवेट क्षेत्र को सौंपने के प्रस्तावित फैसले को विपक्ष ने हिमाचल ऑन सेल की संज्ञा दी है। ऐसे में जब निगम सार्वजनिक रूप से यह कह दे कि उसके यहां से इस आश्य का कोई प्रस्ताव ही नहीं गया तब स्थिति काफी बदल जाती है। क्योंकि आने वाले दिनों में यह फैसले कई विवादों का कारण बनेंगे और तब मंत्रिमंडल की स्वीकृति का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सागर कथा मामले में इस तरह की स्थितियां एक समय प्रदेश में घट चुकी हैं। इसलिये पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष का यह खुलासा की उसकी ओर से कोई प्रस्ताव ही नहीं गया और इसके बाद मंत्रिमंडल का फैसला ले लेना अपने में कई सवाल खड़े कर जाता है।

केन्द्र ने प्रदेश को आपदा की इस घड़ी में भी कुछ नहीं दिया:राजेश धर्माणी

शिमला/शैल। नगर नियोजन, हाउसिंग व तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि राज्य सरकार पूरी

तरह से आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़ी हैं। राज्य सरकार की ओर से आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने प्रभावितों का हौंसला बढ़ाते हुए कहा कि करसोग के आपदा प्रभावितों की भी उसी समान मदद की जाएगी जैसी सराज विधान सभा क्षेत्र में की जाएगी।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों की बहाली और निर्माण कार्य में तकनीक का अधिक उपयोग करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार आपदा की इस घड़ी में भी आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश की अनदेखी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने लैंड स्लाइड जैसी घटनाओं से निपटने के लिए एसडीआरएफ के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को 1 हजार करोड़ से अधिक की राशि दी लेकिन इसमें भी हिमाचल प्रदेश की पूरी तरह से अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने एसडीआरएफ के अंतर्गत असम को 375 करोड़, मणिपुर को 29 करोड़, केरल को 153 करोड़, मेघालय को 30 करोड़, मिजोरम को 22 करोड़ रुपए, उत्तराखंड को 455 करोड़ रुपए जारी किए गए है लेकिन हिमाचल प्रदेश को आपदा की इस घड़ी में भी कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र के भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा क्षेत्र के साथ भी भेदभाव किया गया।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, लेकिन उसके बाद भी हिमाचल प्रदेश की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री भी प्रदेश का पक्ष भारत सरकार के समक्ष रखने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने करसोग में निर्माणाधीन आईटीआई भवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।

उन्होने नगर नियोजन, हाउसिंग व तकनीकी शिक्षा मंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्र सरकोल, कुटी और पुराना बाजार का दौरा भी किया और प्रभावित परिवारों से मिले। वें इस त्रासदी में अपने परिजनों को खोने वाले परिवार के सदस्यों से भी मिले। उन्होंने बताया कि इस त्रासदी से जो परिवार बेघर हो गये हैं, उन्हें किराए के मकान में रहने के लिए राज्य सरकार 5 हजार रुपये प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के साथ राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंडी ज़िला के थुनाग विश्राम गृह में नेता प्रतिपक्ष

जय राम ठाकुर के साथ बैठक कर आपदाग्रस्त सराज क्षेत्र में हुये नुकसान और राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए सड़कों और बाधित जल एवं विद्युत आपूर्ति योजनाओं की बहाली के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर राज्य के लिए एक विशेष राहत पैकेज देने का अनुरोध करेंगे।

सुक्खू ने सम्बंधित विभागों को क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, बिजली और जल परियोजनाओं के लिए अविलम्ब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तत्काल तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि सीआरआईएफ के अंतर्गत 56 किलोमीटर लंबी चौलचौक-जंजैहली सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य प्रस्तावित किए जाएंगे। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर के साथ समन्वय स्थापित कर अंतर-विभागीय सहयोग के माध्यम से प्रमुख योजनाओं की बहाली के लिए राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि भारी तबाही के बावजूद, 60 प्रतिशत पेयजल योजनाओं को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को आवश्यकतानुसार क्षेत्र में बेली पुलों और सस्पेंशन पुलों का निर्माण कर सम्पर्क बहाल करने को कहा जिसके लिए राज्य सरकार पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू और जय राम ठाकुर ने इस आपदा में अपनी जमीन गंवाने वाले परिवारों के पुनर्वास को लेकर चर्चा की। जय राम ठाकुर ने कहा कि बादल फटने की घटनाओं से क्षेत्र में भारी तबाही हुई है और मानसून के बाद जल्द ही सर्दियां शुरू होने वाली हैं। ऐसे में जिन लोगों ने सब कुछ खो दिया है, उनके पुनर्वास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने मंडी के उपायुक्त को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों के अस्थायी पुनर्वास के लिए तुरंत सुरक्षित स्थानों की पहचान की जाए, जहां प्री-फैब्रिकेटिड घर बनाकर उन्हें तत्काल आश्रय दिया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को बागवानी से जुड़े किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने आपदा प्रभावित थुनाग बाजार का निरीक्षण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष

जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपदा प्रभावित थुनाग बाजार का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उन्हें हर सम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

बाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जल्द नई दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। वह हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष सहायता पैकेज की मांग करेंगे ताकि आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के साथ-साथ उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री आपदा में अपनी जवान गंवाने वाले स्थानीय व्यक्ति बुद्धिराज के घर भी पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों का दुःख-दर्द बांटा। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान करेगी।

प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 23 वर्षों के बाद पैरा मेडिकल सीटें बढ़ाई

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने लगभग 23 वर्षों के अंतराल के बाद चिकित्सा क्षेत्र में तकनीशियन पाठयक्रमों के लिए सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी के दृष्टिगत लिया गया है। इससे लंबे समय से प्रदेशभर में गुणात्मक स्वास्थ्य देखभाल सेवायें प्रदान करने पर प्रभाव पड़ रहा है और आधुनिक मशीनों तथा अन्य उपकरणों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित श्रम शक्ति की आवश्यकता है और इस निर्णय से प्रदेश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में पैरामेडिकल स्टाफ की सीटें बहुत कम हैं और प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला तथा डॉ. राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, जिला कांगड़ा में यह सीटें को बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आईजीएमसी शिमला में बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक, बीएससी रेडियो और इमेजिंग, बीएससी एनेस्थीसिया और ओटी तकनीक में प्रत्येक पाठयक्रम की सीटें 10 से बढ़ाकर 50 की गई हैं। डॉ. राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक, बीएससी रेडियोलॉजी और इमेजिंग तथा बीएससी एनेस्थीसिया और ओटी तकनीक में प्रत्येक पाठयक्रम की सीटें 18 से बढ़ाकर 50 की गई हैं, ताकि प्रदेश के युवाओं को राज्य में ही प्रशिक्षण प्राप्त हो सके।

उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी से राज्य के अधिक युवाओं को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा, जिससे उन्हें राज्य के बाहर स्थित संस्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में पदों का सृजन और उन्हें भरने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इसके अलावा, नर्सिंग और पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए प्रशिक्षण के अवसर भी बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

अगस्त माह से मिलेगी गौपाल योजना की बढ़ी प्रोत्साहन राशि: चंद्र कुमार

शिमला/शैल। पशुपालन एवं कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गौसेवा आयोग द्वारा गौपाल योजना के अंतर्गत प्रति माह प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 700 रुपये से 1200 रुपये प्रतिमाह प्रति गौवंश बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि गौ-सदनों को यह राशि अगस्त, 2025 से उपलब्ध करवाई जाएगी।

पशुपालन एवं कृषि मंत्री गौसेवा आयोग की 6वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान प्रदेश में गौसदनों की स्थापना, संचालन व बेसहारा गौवंश के पुनर्वास पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 276 गौसदनों और गौ-अभ्यारण्यों में 21,306 बेसहारा गौवंश को आश्रय प्रदान किया जा रहा है। जिला कांगड़ा, हमीरपुर व ऊना में नए गौ-सदनों और गौ-अभ्यारण्यों को स्थापित करने का कार्य जारी है।

आयोग ने कृषि विभाग की सहायता से गौ-सदनों और गौ-अभ्यारण्यों में बायोगैस प्लांट स्थापित करवाने का निर्णय लिया। पशुपालन मंत्री ने पशुपालन विभाग द्वारा सभी गौ-सदनों और गौ-अभ्यारण्यों में नियमित पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने और इनका उचित अभिलेख रखने के निर्देश दिए। प्रदेश की सीमाओं में लगते राज्यों से पशु तस्करी और आवारा पशु छोड़ने के मामलों में पुलिस विभाग को आवश्यक कारवाई करने के आदेश दिए।

बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि आयोग भाषा एवं संस्कृति विभाग के साथ मिलकर गौ-सदनों व गौ-अभ्यारण्यों के निर्माण एवं संचालन के लिए एक नीति निर्धारण करेगा जिसमें सामुदायिक भागीदारी को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा।

सार्वजनिक और निजी परिसरों में लिफ्ट सुरक्षा नियम सख्ती से होंगे लागू: डॉ. जैन

शिमला/शैल। सचिव, लोक निर्माण विभाग डॉ.अभिषेक जैन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश लिफ्ट अधिनियम, 2009 के तहत कोई भी व्यक्ति जो अपने परिसर में लिफ्ट लगाना चाहता है, उसे लिफ्ट स्थापित होने के एक महीने के भीतर अनुमति और लाइसेंस के लिए आवेदन करना जरूरी है। 31 अगस्त 2024 तक पूरे प्रदेश में केवल 1000 लिफ्टें ही पंजीकृत थीं, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 1900 हो गई है।

उन्होंने बताया कि लिफ्टों की स्वीकृति और लाइसेंस से जुड़े सभी कार्यों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जिससे लोगों में लिफ्टों की सुरक्षा को लेकर विश्वास पैदा हो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

जैन ने बताया कि जो लोग लिफ्ट लगाना चाहते हैं, वे edistrict .hp.gov.in वेबसाइट पर जाकर नागरिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब पंजीकरण, अनुमति और नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है और शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश के दृष्टिगत लिया गया है। लिफ्टों का समय-समय पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और लिफ्ट सुरक्षा नियमों का पालन करने से पर्यटकों की सुरक्षा सुनिशिचत होगी और उनमें विश्वास भी बढ़ेगा।

डॉ. जैन ने बताया कि जून 2025 तक 3500 लिफ्ट निरीक्षण किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल अगस्त तक केवल 750 निरीक्षण हुए थे। अधिनियम के अनुसार, हर लिफ्ट के भीतर उसका पंजीकरण और लाइसेंस की प्रति लगाना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश के होटलों, सरकारी कार्यालयों तथा अन्य सार्वजनिक और निजी इमारतों में लगभग 3500 लिफ्टें संचालित की जा रही हैं। अगस्त 2024 तक लगभग 2500 लिफ्टें बिना पंजीकरण के थीं, जिनमें से अब केवल 1500 लिफ्टों का पंजीकरण बाकी है। इन मामलों में नोटिस भी जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इससे राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अधिनियम लागू होने के बाद 16 वर्षों में मात्र 7.5 लाख रुपये का राजस्व मिला था, जबकि फरवरी 2025 से जून 2025 तक 5.58 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा जांच और स्वत: नवीनीकरण की सुविधा के कारण लिफ्ट दुर्घटनाओं में कमी आई है और लोगों में सुरक्षा को लेकर विश्वास भी बढ़ा है।

साथ ही इस प्रणाली ने डिजीटल रिकार्ड कीपिंग को व्यापक रूप से लागू किया है जिसे पारदर्शी ऑडिट ट्रेलस तैयार हुए हैं जो अनाधिकृत इंस्टॉलेशन को रोकते हैं और कानूनी मानदण्डों का पालन सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन शुल्क संग्रह की प्रक्रिया में वित्तीय हानियों को कम किया है जिससे अनुमोदन, नवीनीकरण और निरीक्षण के लिए समय पर भुगतान सम्भव हो पाया है और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हुई है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक: जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

स्टेट ओवरसाइट कमेटी की बैठक में कारागार एवं सुधार गृह के कार्यों की समीक्षा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना निदेशक राजीव कुमार की अध्यक्षता में स्टेट ओवरसाइट कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कारागार एवं सुधार गृह तथा अन्य

क्लोज सेटिंग में चलाए जा रहे कार्यों की वर्ष 2025-26 (अप्रैल से जून माह) की समीक्षा की गई।

परियोजना निदेशक राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत सभी जेलों के प्रत्येक कैदियों की एचआईवी, सिफलिस, टीबी, हेपेटाइटिस आदि की जांच सुनिश्चित करवाई जाये। इससे नाको के 95-95-95 का लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा तथा समस्त कैदियों के स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो कैदी संक्रमित पाये जाते हैं, उन्हें जेल व स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मजबूत समन्वय स्थापित कर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाये। उन्होंने प्रदेश में कैदियों के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक में कारागार एवं सुधार गृह, पुलिस, राज्य महिला एवं बाल विकास, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन टीबी, राज्य हेपेटाइटिस नियंत्रण, राज्य एड्स नियंत्रण विभाग के समस्त अनुभाग, दिशा टीम व सहायक भागीदारी एचएलएफपीपीटी संस्था के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

रजिस्ट्री के लिए अब केवल एक बार जाना होगा कार्यालय:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 'माई डीड' एनजीडीआरएस नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करते हुये कहा कि नागरिकों को अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए केवल एक बार कार्यालय जाना होगा। वे किसी भी समय और कहीं से भी भूमि पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिससे उनका समय और श्रम बचेगा। इस पहल से जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। बिलासपुर जिले की बिलासपुर सदर तहसील, जिला चम्बा की डलहौजी तहसील, जिला हमीरपुर की गलोड़ तहसील, जिला कांगड़ा की जयसिंहपुर तहसील, जिला कुल्लू की भूंतर, जिला मंडी की पधर तहसील, जिला शिमला की कुमारसेन, जिला सिरमौर की राजगढ़, जिला सोलन की कंडाघाट तहसील तथा जिला ऊना की बंगाणा तहसील में इस परियोजना का शुभारम्भ किया गया है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जमाबंदी, ई-रोजनामचा वाक्याती और कारगुजारी पहलों का भी शुभारंभ किया, ताकि राजस्व विभाग के कार्यो को और बेहतर बनाया जा सके और लोगों के लिए पंजीकरण व अन्य प्रक्रियाएं प्रक्रियाएं सरल व सुगम हो सकें।

उन्होंने कहा कि नई जमाबंदी का प्रारूप सरल हिंदी में तैयार किया गया है। इसमें अब उर्दू, अरबी और फारसी जैसी पुरानी भाषाओं को हटाया गया है ताकि आम लोग भूमि रिकॉर्ड को आसानी से समझ सकें। ई-रोजनामचा वाक्याती से पटवारियों को प्रतिदिन की गतिविधियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में सुविधा मिलेगी, जबकि कारगुजारी प्रणाली से वे अपनी दैनिक हाजिरी ऑनलाइन लगा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से अब तहसीलदार

भी अपने कार्यो की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। जल्द ही ऑनलाइन म्यूटेशन रजिस्टर को भी इस पहल से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमें ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ना है जो पेपरलेस, प्रजेंसलेस और कैशलेस हो ताकि लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं सुनिश्चित हो सकें।

उन्होंने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी और डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग को निर्देश दिए कि राजस्व सेवाओं को अधिक प्रभावी और जन हितैषी बनाने के लिए विभिन्न डिजिटल मॉडयूल्स पर तेजी से कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने 10 दिनों के भीतर डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी मॉडयूल तैयार करने के भी निर्देश दिए ताकि लोगों को 'फर्द' भूमि रिकॉर्ड की प्रति प्राप्त करने के लिए पटवारखानों के चक्कर न काटने पड़ें।

मुख्यमंत्री ने 15 दिनों के भीतर एक ऑनलाइन, पेपरलेस राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे लोग ऑनलाइन याचिकाएं दायर तथा समन व अपडेट डिजिटल माध्यम से प्राप्त कर सकें। उन्होंने एनआईसी को यह भी निर्देश दिए कि 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन म्यूटेशन मॉडयूल विकसित किया जाए और इसे जमाबंदी रिकॉर्ड से सीधे जोड़ा जाये, जिससे म्यूटेशन पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे इन सभी पहलों को ज़मीनी स्तर पर सक्रिय रूप से लागू करें ताकि लोग इन डिजिटल सेवाओं का पूर्ण लाभ उठा सकें। उन्होंने विशेष रूप से उन मामलों में जहां भूमि एक से अधिक लोगों के संयुक्त नाम पर है के लिए 'खान्गी तकसीम' को मिशन मोड में अपनाने के भी निर्देश दिए। इससे 'सिंगल खाता, सिंगल ओनर' की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा और भूमि रिकॉर्ड अधिक सरल व स्पष्ट बनेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये डिजिटल सुधार लोगों की सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता को कम करेंगे। इन प्रयासों से जन समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा और लोगों को राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य की ऋण सीमा बढ़ाने का आग्रह किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति से अवगत करवाया और प्रदेश की ऋण सीमा बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने जानकारी दी कि हाल ही में भारी बारिश के कारण प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य को सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने वित्त मंत्रालय में प्रदेश के लम्बित विभिन्न मामलों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने नाचन क्षेत्र के बागा, स्यांज व पंगल्यूर गांव में आपदा का जायजा लिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू मण्डी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित परिवारों से मिले और उनका

मनोबल बढ़ाया। उन्होंने आपदा प्रभावित बागा, स्यांज, पंगल्यूर गांव में हुए नुकसान का निरीक्षण किया। उन्होंने आपदा में मारे गए व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और प्रभावितों को राज्य सरकार की ओर से उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने प्रभावितों से उनकी संपत्ति को हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी ली। प्रभावितों की बात सुनकर मुख्यमंत्री व्यथित हो गए। रास्ते में अनेक स्थानों पर रुककर मुख्यमंत्री ने लोगों की बात को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि आपदा बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन राज्य सरकार हर प्रभावित का पुनर्वास करेगी और उनकी मदद करेगी।

नाचन विधानसभा क्षेत्र के बागा में दो व्यक्तियों की मौत हुई है जबकि पंगलयूर गांव में नौ लोग बह गये, जिनमें से चार शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 5 व्यक्ति अभी भी लापता हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके दर्द को जानती है और इस दुःखद् समय में उनके साथ खड़ी है। बागा में प्रभावितों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पूरा पहाड़ खिसक आया और जान माल का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रभावितों से कहा कि घर, गौशाला, गाय, भेड़ बकरी और गौशाला को हुए नुकसान का पूरा मुआवजा राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावितों के लिए रहन-सहन के लिए बेहतर तथा समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने शोघी – ढली फोरलेन परियोजना के संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला शिमला में निर्माणाधीन 27 किलोमीटर लंबे शोघी-ढली फोरलेन मार्ग के विभिन्न संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने भट्टाकुफर, संजौली, ढली, लिंडीधार और आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं।

स्थानीय निवासियों ने एनएचएआई द्वारा पहाड़ियों के कटान की गतिविधियों को लेकर गहरी चिंता जताई जिनके कारण क्षेत्र में भू-स्खलन जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। इससे लोगों की निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है तथा जान-माल पर खतरा बना है। चलौंठी निवासी संजय शर्मा ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि मैं पहले किराये पर मकान देता था, लेकिन अब खुद किरायेदार बन गया हूं क्योंकि मेरा भवन असुरक्षित हो गया है।

लिंडीधार में एक अन्य निवासी ने कहा कि एनएचएआई अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। हमने अपनी संपत्तियों का भारी नुकसान झेला है और अब हमारे सिर पर हर समय खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप कर जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की।

लोगों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को तुरंत आवश्यक कदम उठाने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोग वर्षो की मेहनत और बचत से घर बनाते हैं। जब ऐसे घर

गिरते हैं तो यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक आघात भी होता है। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र इस मामले को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाएंगे।

मुख्यमंत्री ने असुरक्षित भवनों में रहने वाले परिवारों को राज्य सरकार की ओर से मकान किराये के रूप में प्रतिमाह 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, आपदा में नुकसान झेलने वाले परिवारों को विशेष राहत पैकेज भी दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ऐसे निर्माण कार्यों के ठेके स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाने चाहिए क्योंकि वे पहाड़ी इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियों से बेहतर रूप से परिचित होते हैं। साथ ही, उन्होंने एनएचएआई से आधुनिक तकनीकों को अपनाने और पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंग आधारित विकल्पों की संभावनाएं तलाशने को कहा ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचा जा सके।

शिमला जिला प्रशासन ने फोरलेन मार्ग के संवेदनशील स्थलों की पहचान और समाधान के सुझाव देने के लिए अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, भट्टाकुफर में हाल ही में हुए भवन गिरने की घटना की जांच के लिए अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, उपायुक्त अनुपम कश्यप और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने रहस्यमयी सेब रोग की वैज्ञानिक जांच के निर्देश दिए

शिमला/शैल। सेब उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट कर, सेब के बगीचों में तेजी से फैल रही एक नई बीमारी से अवगत करवाया। इस बीमारी से उनकी फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से इस बीमारी की वैज्ञानिक जांच तथा नियंत्रण के लिए शीघ्र कारवाई करने का आग्रह किया। बागवानों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस बीमारी के कारण सेब के पत्ते पीले पड़ रहे हैं तथा समय से पहले ही गिरने लगे हैं, जिससे सेब की पैदावार में भारी गिरावट आ रही है।

मुख्यमंत्री ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, जिला सोलन के कुलपति से दूरभाष पर बात की तथा विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ टीमों को अविलम्ब प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस बीमारी की वैज्ञानिक जांच की जाये तथा बागवानों को जमीनी स्तर पर रोकथाम एवं नियंत्रण उपायों बारे शिक्षित किया जाये।

मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बीमारी तेजी से फैल रही है तथा बागवानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस स्थिति से यथाशीघ्र निपटना जरूरी है। उन्होंने कुलपति को सात दिनों के भीतर प्रदेश सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि यथाशीघ्र उचित कदम उठाए जा सकें। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार किसानों और फल उत्पादकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादन राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और हजारों परिवार इस क्षेत्र से अपनी आजीविका कमाते हैं।

सत्य की खोज करने वाले को धूल से भी अधिक विनम्र होना चाहिए।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

पेड़ काटकर अतिक्रमणों से बेदखली कितनी संभव हो पायेगी?

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वन विभाग ने वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से कर दी है। सैंकड़ो सब के पेड़ काट दिये गये हैं। इन पेड़ों को काटने और उस पर होने वाले अन्य खर्चो की वसूली अतिक्रमणकर्ताओं से वसूलने के भी आदेश अदालत ने पारित किये हैं। अदालत की यह कारवाई भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 163 के तहत की जा रही है। मान्य अदालत को यह आदेश इसलिये पारित करने पड़े हैं क्योंकि उसके पास ऐसे अतिक्रमणों को नियमित करने की सरकार की ओर से न तो कोई पॉलिसी रखी गई और न ही ऐसी योजना प्रस्तावित होना सामने आया है। इन पेड़ों को काटे जाने पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं उभर रही हैं। इस मामले का राजनीतिक प्रतिफल अवश्य होगा। इसलिये इस पर व्यापक चर्चा उठाने की आवश्यकता हो जाती है। स्मरणीय है कि आपातकाल के दौरान 1975 में हर भूमिहीन ग्रामीण को दस कनाल/पांच बीघा जमीन दी गयी थी। सरकार की ओर से बाद में ऐसी जमीनों पर उगे पेड़ों का अधिकार भी इन लोगों को दे दिया गया था। इसी के साथ यह भी स्मरणीय है कि वन अधिकार कानून केंद्र सरकार का एक विशेष कानून है जो अन्य कानूनों पर भी प्रभावी होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 18-4-2013 को उड़ीसा खनन निगम मामले में स्पष्ट कहा है कि जब तक वन अधिकारों का सत्यापन नहीं हो जाता तब तक वन भूमि से बेदखली को अंजाम न दिया जाये। हिमाचल में इन वन अधिकारों की विवेचना शायद अब तक नहीं हो पायी है। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत सारी चीजों के लिये वनों पर आधारित रहते हैं। इसलिये वन अधिकारों की विवेचना और सत्यापन होना आवश्यक है।

हिमाचल सरकार ने वर्ष 2000 में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को नियमित करने की एक योजना बनाई थी। इस योजना के तहत लोगों ने स्वेच्छा से शपथ पत्रों पर अतिक्रमण की जानकारी दी थी। उसके मुताबिक 1,23,835 बीघे में 57549 मामले विभिन्न अदालतों में लंबित चल रहे थे। वैसे प्रारंभिक जानकारी में तीन लाख मामले संज्ञान में आने की बात कही गयी थी। इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों और सैनिक विधवाओं को विशेष लाभ देने की योजना थी। लेकिन इस योजना को उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गयी और यह लागू नहीं हो पायी। लेकिन जब प्रदेश में इतने स्तर पर अतिक्रमण के मामले सामने आ गये तब राज्य सरकार का दायित्व बनता था कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर वनाधिकार अधिनियम के साये में इसका हल तलाशते। 2014-15 से यह मामला प्रदेश उच्च न्यायालय के सामने जनहित याचिकाओं के माध्यम से सामने है। एनजीटी ने भी इसका संज्ञान लिया है। वहां पर पीसीसीएफ ने शपथ पत्र देकर जानकारी दी है कि 2001 से 2023 के बीच 5689 है0 वन भूमि पर 80374 अतिक्रमण के मामले पाये गये हैं। इनमें से 3097 है0 में 9903 मामलों को सफलता पूर्वक बेदखल कर दिया गया है। अब 1995 के गोदावरमन मामले में मई 2025 में आये फैसले में अतिक्रमणों को चिन्हित करने के लिये हर जिले में डीआरओ और डीएफओ के तहत एसआईटी गठित कर दी गयी है। इनकी रिपोर्ट आने का इंतजार है।

अतिक्रमण के इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है। इतना बड़ा अतिक्रमण राजस्व और वन अधिकारियों तथा राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है। इसलिये वनाधिकार अधिनियम के साये में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर इसका स्थायी हल खोजना होगा। क्योंकि इतने बड़े स्तर पर पेड़ काटकर बेदखली करने से इसका हल नहीं होगा।

भारतीय बहुलवाद संस्कृति और दाऊदी बोहरा समुदाय, आधुनिकता और धार्मिकता का उदाहरण

गौतम चौधरी

भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता की विशाल कैनवास में दाऊदी बोहरा समुदाय एक शांत लेकिन प्रभावशाली उदाहरण के रूप में खड़ा है। कर्तव्य, व्यापारिक उद्यमिता और अन्य धार्मिक समूहों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का उदाहरण खासकर अन्य मुस्लिम समाज में देखने को कम ही मिलता है। बोहरा, इस्माइली शिया मुस्लिमों का एक उप-संप्रदाय है, जिनकी वैश्विक आबादी लगभग दस लाख है। हालांकि इस समुदाय में कुछ सुन्नी मुसलमान भी हैं लेकिन दोनों की प्रकृति लगभग एक जैसी ही होती है। भारत में ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में विशेष रूप से बसे हुए हैं। ये लोग अब भारतीय ही हैं लेकिन इनका दावा है कि इनके पूर्वज, इस्लाम के अंतिम नबी, हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के परिवार से तालुकात रखते थे। इस समुदाय के लोगों का यह भी दावा है कि किसी समय अफ्रीका के उत्तरी भाग पर उनका शासन था और मिस्र के काहिरा में जो इस्लामिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है वह उनके पूर्वजों के द्वारा ही की गयी। उत्तरी अफ्रीका में शासन के अंत के बाद इस समुदाय के लोग भारत के तटवर्ती क्षेत्र में आकर बसने लगे। यहां के हिन्दू राजाओं ने इनका संरक्षण और पोषण किया। इसके बाद इस समुदाय के लोग फिर भारत के ही होकर रह गए। बाद के दिनों में बोहरा समुदाय के लोग मध्य-पूर्व, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर आदि देश में जाकर बसे हैं। कुछ बोहरा प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों में भी जाकर बसे हैं।

बोहरा समाज के पेशेवर और व्यापारी भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह समुदाय ऐसे विवादों से दूर रहते हैं जो भारत में नकारात्मक सुर्खियां बनते रहे हैं। इस समुदाय को भारत ही नहीं दुनिया में इसलिए जाना जाता है कि ये जहा कहीं भी निवास करते वहां की संस्कृति और राष्ट्र जीवन को ध्यान में रखकर अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। बोहरा समुदाय मुसलमानों के लिए ही नहीं अन्य धार्मिक समुदायों के लिए एक उदाहरण हैं, धार्मिकता के साथ आधुनिकता भी है। यानी इस समाज का लगभग प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक के साथ आधुनिक भी है। भारत में इनकी आमद यह दर्शाती है कि कोई व्यक्ति धार्मिक भी हो सकता है और आधुनिक भी, पारंपरिक भी हो सकता है और प्रगतिशील भी और पूरी तरह से भारतीय होते हुए भी वैश्विक चिंतन से ओतप्रोत हो सकता है।

इनकी धार्मिक जड़ें फातिमी मिस्र से जुड़ी हैं और ये लोग 11वीं शताब्दी में भारत आए। इतने वर्षो में इन्होंने भारतीय समाज में न केवल खुद को समाहित किया, बल्कि जिस क्षेत्रों में ये बसे, वहां के आर्थिक और नागरिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने की पूरी कोशिश की। दाऊदी बोहरा समुदाय अपने मजबूत व्यापारिक नैतिक मूल्यों के लिए जाना जाता है और व्यापार, निर्माण व उद्यमिता में सफलता प्राप्त की। सूरत, उदयपुर और मुंबई जैसे शहरों में इनके व्यापारिक नेटवर्क खूब फले-फूले हैं। ये नेटवर्क ईमानदारी, पारदर्शिता और स्थिरता जैसे मूल्यों पर आधारित हैं, जिससे इन्हें धार्मिक और भाषाई सीमाओं के पार जाकर सम्मान मिला है। आज जब धनार्जन को सामाजिक जिम्मेदारी से अलग समझा जाता है, तब बोहरा समुदाय यह साबित करता है कि सामुदायिक नैतिकता को अपनाकर भी समृद्ध हुआ जा सकता है।

समुदाय की सामाजिक संस्थाएं मुस्लिम दुनिया में सबसे प्रभावशाली मानी जाती हैं। मुंबई स्थित इनका केंद्रीय नेतृत्व प्रणाली, दाई अल-मुतलक के अधीन है। यह संसाधनों को संगठित करने, जनकल्याण योजनाओं को लागू करने और सामूहिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए जाना जाता है। फैज़ अल-मवाइद अल-बुरहानिया नामक सामुदायिक रसोई योजना के तहत हर बोहरा परिवार को प्रतिदिन ताजा और पौष्टिक भोजन मिलता है। इससे खाद्य अपव्यय कम होता है, सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं और परिवारों का दैनिक बोझ घटता है। समुदाय द्वारा संचालित स्कूल और कॉलेज लड़कों व लड़कियों दोनों को धार्मिक व आधुनिक शिक्षा देते हैं और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। विशेष रूप से बोहरा महिलाओं में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है।

इनके द्वारा शहरों की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी गहरी प्रतिबद्धता दिखाई देती है। स्वच्छ भारत अभियान जैसी पहलों में भागीदारी और नियमित स्वच्छता अभियान इस बात का उदाहरण हैं कि धार्मिक पहचान और राष्ट्रीय हित कैसे एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं। मुंबई की हाल ही में पुनर्निर्मित सैफी मस्जिद केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि वास्तुशिल्प धरोहर और सामुदायिक गर्व का प्रतीक है। इसके निर्माण में पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल विधियों का उपयोग किया गया, जो अतीत के प्रति श्रद्धा और भविष्य की चिंता दोनों को दर्शाता है।

सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि दाऊदी बोहरा समुदाय अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखते हुए भी संकीर्ण नहीं है। वे पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, लिसान अल-दावत नामक मिश्रित भाषा बोलते हैं (जो गुजराती, अरबी और उर्दू का संयोजन है), और अपने विशिष्ट रीति-रिवाजों का पालन करते हैं। फिर भी, वे देश के लोकतांत्रिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। इन्हें शायद ही कभी सांप्रदायिक हिंसा या कट्टरता से जोड़ा गया। ये लोग शालीनता, संवाद की वरीयता और संघर्षो के समय शांतिपूर्ण कूटनीति के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा कानून का पालन, अंतरधार्मिक सम्मान और सामाजिक सौहार्द पर बल दिया जाता है, जो धार्मिक सह-अस्तित्व का एक उच्च आदर्श प्रस्तुत करता है।

इस समुदाय की जीवन यात्रा में समुदाय के नेतृत्व की अहम भूमिका रही है। दिवंगत सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन और उनके उत्तराधिकारी सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों से अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, सभी भारतीय नेताओं ने बोहरा नेताओं के योगदान की सराहना की है और उनके एकता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के संदेश से प्रेरणा ली है। ये रिश्ते इस बात को उजागर करते हैं कि जब कोई समुदाय राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करता है, तो विशेषाधिकार की मांग किए बिना भी उसे विशिष्टता प्राप्त हो जाती है। वह स्थानीय लोगों का दिल जीत लेता है और कालांतर में अपने व्यवहार के बल पर आगे की पंक्ति में अपना स्थान सुरक्षित कर लेता है।

धार्मिक समुदायों की आलोचना में अक्सर आंतरिक पदानुक्रम और पुरोहितवादी सत्ता का उल्लेख होता है। ये चिंताएं विचार और विमर्श की मांग करती हैं। फिर भी यह भी सच है कि बोहरा समुदाय ने बदलाव के लिए तत्परता दिखाई है। बोहरा महिलाएं अब शिक्षा, व्यवसाय और संवाद में बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं, वह भी अपने सांस्कृतिक ढांचे के भीतर रहकर। बाहरी दबाव में झुकने की बजाय, यह समुदाय भीतर से परिवर्तन की दिशा में शांतिपूर्ण प्रयास कर रहा है। यह मॉडल पहचान संकट और सांस्कृतिक ध्रुवीकरण के समय में एक रचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में जहां मुसलमानों को या तो पीड़ित या खतरे के रूप में देखा जाता है, बोहरा समुदाय इन रूढ़ छवि को चुनौती देता दिखता है। यह सिद्ध करता है कि आस्था प्रगति में बाधा नहीं है और धार्मिक निष्ठा संविधानिक मूल्यों के साथ सामंजस्य बैठा सकती है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि बहुलवाद केवल संविधान में दिया गया वादा नहीं है, बल्कि यह एक दैनिक अभ्यास है, जो भव्य वक्तव्यों में नहीं, बल्कि नागरिक जिम्मेदारी, पारस्परिक सम्मान और नैतिक जीवन के सामान्य कार्यो में प्रकट होता है। ऐसे समय में जब भारत नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर जटिल बहसों से गुजर रहा है, बोहरा अनुभव बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, एक कठोर मॉडल के रूप में नहीं, बल्कि यह स्मरण कराने के लिए कि सांस्कृतिक विविधता राष्ट्रीय एकता को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत कर सकती है। दाऊदी बोहरा कोई अपवाद नहीं हैं, वे इस बात का प्रमाण हैं कि वैकल्पिक सकारात्मकता संभव हैं, जो विश्वास, परिश्रम और शांत जैसे गरिमामय और उच्च मूल्य वाले व्यवहार पर आधारित हों।

गुरु पूर्णिमा: मानवता को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने वाला पर्व

अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)
और संसदीय कार्य राज्य मंत्री,
भारत सरकार

भारत की सांस्कृतिक विरासत हमें मानवीय मूल्यों से परिचित कराती है तथा ज्ञान और शाश्वत शिक्षा प्रदान करती है। इसका विविध एवं सर्वव्यापी स्वरूप सामूहिक चेतना को जागृत करता है जिसकी अभिव्यक्ति भारत में मनाये जाने वाले विभिन्न त्यौहारों के रूप में होती है। ये त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं हैं बल्कि ये हमारी प्रकृति के साथ जुड़ाव तथा वैज्ञानिक सोच एवं आध्यात्मिक चिंतन से जुड़े हैं। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा ही विशेष अवसर है जो हमें इतिहास में घटित घटनाओं के बारे में रूककर विचार करने और उन्हें समझने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें यह जानने के लिए प्रोत्साहित करता है कि विगत की परिस्थितियों में अब क्या बदलाव आया है, किन बातों को हम अभी भी अपनाए हुए हैं और हमने अपने पीछे क्या कुछ छोड़ दिया है? हमने व्यक्ति के रूप में कितनी और सामूहिक रूप में कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं? अपनाने और छोड़ने के इस दौर में हमारा साथ किन लोगों ने सबसे अधिक दिया? जीवन के उथल-पुथल एवं दुख से भरे समय में जबकि हमारा काफी अधिक पतन हो सकता था वैसे अस्थिर समय में किसने हमारा साथ दिया? ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जिनके समाधान के लिए हमें गुरु या एक पथ-प्रदर्शक शक्ति की सर्वाधिक अहम भूमिका होती है चाहे वह कोई व्यक्ति हो, सिद्धांत हो या हमारे अंतर्मन की शक्ति हो जो हमारी जीवन यात्रा के दौरान सर्वाधिक शक्तिशाली मित्र के रूप में हमारा साथ निभाती है। समय की कसौटी पर खरे उत्तरे वे कौन से सिद्धांत हैं, जो हमें जीवन के पथ पर एक संतुलित यात्री बने रहने में सफल बनाते हैं। हमारे जीवन की इन सभी विविध परिस्थितियों के बीच प्राय: अदृश्य अथवा दृश्य, मूर्त या अमूर्त ऐसी शक्तियां होती हैं चाहे वो किसी पथ-प्रदर्शक का हाथ हो या कोई दिव्य विचार हो, मां का सानिध्य हो, शिक्षक के ज्ञान भरे शब्द हों या किसी मित्र का साथ हो जो हमारा पथ-प्रदर्शक बन जाता है। अत: गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी शक्तियों को चाहे वह दृश्य हों अथवा अदृश्य, जो हमारा मार्गदर्शन करती हों, हमें सही रूप में ढालती हों और हमारे जीवन में उन्नति के पथ पर हमारा साथ देती हों, सभी को सम्मानित करने का एक पवित्र अवसर है।

गुरु पूर्णिमा का त्योहार व्यक्ति के जीवन और उसके सामाजिक मूल्यों को एक सही रूप में ढालने में गुरु की भूमिका को सम्मानित करने की एक शाश्वत परंपरा है। आसाढ़ मास की पूर्णिमा के इस दिन का गहरा आध्यात्मिक, ऐतिहासिक तथा सामयिक महत्व है क्योंकि इसी दिन आदिगुरु भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान प्रदान किया था। इसी दिन महर्षि वेदव्यास की जन्म जयंती भी मनाई जाती है। इसके साथ ही, पूर्णिमा के दिन से चतुर्मास आरंभ होते हैं जो मानसून के दौरान के पवित्र चार महीने हैं जबकि साधु-संत किसी एक ही स्थान पर रहकर अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं। आसाढ़ मास की पूर्णिमा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चांद के शीतल प्रकाश की ऊर्जा हमारे आंतरिक मन को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करती है। गुरु पूर्णिमा का यह त्योहार हमें उन लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है जिन्होंने हमारे मन में ज्ञान की ज्योति जगाई है।

संस्कृत शब्द-''गुरु'' दो शब्दों 'गु'-अंधकार और-'रु' हटाना का संयोजन है जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे मन से अंधकार अर्थात अज्ञानता को दूर करता हो। प्राचीन वैदिक परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा शिक्षा का आधार थी। गुरुकुल में शिक्षार्थियों को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करके उन्हें विचारशील बनाया जाता था तथा नैतिकता का पाठ पढ़ाकर उनकी नैतिक दुविधाओं का समाधान किया जाता था।

गुरुकुल में शिक्षा की यह प्रक्रिया शिक्षार्थियों को कर्म के माध्यम से मूल्य आधारित जीवन जीने व चरित्र निर्माण करने के लिए निरंतर प्रेरित करने की प्रक्रिया थी। गुरु के महत्व और महानता को केवल शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। गुरु मात्र एक शिक्षक ही नहीं होते बल्कि उनकी उपस्थिति ही एक ऐसी जीवंत शक्ति, एक ऐसी अनुभूति होती है जो शक्ति, मार्गदर्शन और प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत होती है। जिस प्रकार पूर्णिमा संपूर्णता, शुद्धता और प्रकाश का प्रतीक है ठीक उसी प्रकार गुरु में भी वैसी ही महानता होती है और गुरु भी ज्ञान से संपूर्ण, निष्कपट और मन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के स्रोत होते हैं।

प्रसिद्ध संत कबीर ने गुरु की तुलना कुम्हार से और शिष्य की तुलना मिट्टी के कच्चे बर्तन से करते हुए कहा है कि,

''गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ है, गढ़ि-गढ़ि काढ़ै खोट। अंतर हाथ सहार दै, बाहर बाहै चोट।।''

इसका अर्थ है: गुरु कुम्हार है और शिष्य मिट्टी का घड़ा है। जिस प्रकार कुम्हार घड़े को भीतर से हाथ का सहारा देकर और बाहर से चोट मारकर गढ़ता है, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को भीतर से प्रेम, करुणा और ज्ञान का सहारा देकर और बाहर से डांट-फटकार लगाकर उसकी बुराइयों को दूर करता है और उसे अनुशासित व परिष्कृत करता है।

गुरु एक छिपे हुए और कभी भी खत्म न होने वाले ज्ञान का भंडार है -उनके आशीर्वाद मौन होते हुए भी जीवन में आमूल बदलाव लाने वाले होते हैं और शिष्य के मन में सच्चाई और अच्छाई से जुड़े मूल्यों से युक्त ज्ञान व बुद्धिमत्ता भरते हैं। रामायण काल में विश्वामित्र और भगवान राम के बीच तथा भक्तिकाल में गुरु रविदास और मीरा बाई, रामानंद और कबीर, गुरु नानक देव जी और उनके बाद हुए गुरुओं के बीच का संबंध-सभी भारतीय सभ्यता में आध्यात्मिक और बौद्धिक आदान-प्रदान की अमिट विरासत के उदाहरण हैं। इन पवित्र बंधनों ने समाज को एक नैतिक ढांचा प्रदान किया और इसके आंतरिक विकास को बढ़ावा दिया। आधुनिक युग में, देश के लोगों के मन में राष्ट्रवाद की अलख जगाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज तथा समाज को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने में समर्थ गुरु रामदास, स्वामी विरजानंद सरस्वती और स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। इसी गुरु परंपरा में स्वामी राम ष्ण परमहंस भी हुए हैं जिनकी शिक्षा ने स्वामी विवेकानंद को एक आध्यात्मिक महापुरुष बनाया, जिन्होंने बाद में भारतीय दर्शन को पाश्चात्य देशों तक पहुँचाया। इसी प्रकार, महावतार बाबाजी, लाहिड़ी महाशय, श्री युक्तेश्वर और परमहंस योगानंद जैसे महापुरुषों द्वारा दिए गए ज्ञान की ज्योति दुनिया भर के साधकों का मार्गदर्शन करती रहेगी और उन्हें अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान ने विश्व-बंधुत्व की भावना को बढ़ाया है और लोगों को ज्ञान की दिव्य दृष्टि प्रदान की है। विश्व के सभी देशों में देवत्व के प्रति निष्ठा, समर्पण और व्यक्तिगत संबंध को अभिव्यक्त करने की परंपरा देखी जाती है। पश्चिमी देशों में ईश्वर की प्रार्थना के दौरान 'ओ माई मास्टर' शब्द का प्रयोग किया जाता है जो ईश्वर के साथ गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव का सूचक है।

प्रथम गुरु के रूप में मां शिशु को इस नए विश्व से परिचित कराती है और जीवन में पहला कदम उठाना सिखाती है। अगर दूसरे नजरिये से देखा जाए तो हमारी पांचों ज्ञानेन्द्रियां- कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नाक -बाहरी दुनिया से संवेदी सूचनाएं प्राप्त करती हैं, पांचों कर्मेन्द्रियां-हाथ, पांव, वाणी, गुदा, जननांग-शारीरिक क्रियाएं करती हैं तथा अंत:करण की चारों वृत्तियां-मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। यदि संक्षेप में कहा जाए तो, हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रत्यक्ष जगत से प्राप्त जानकारियों को एकत्र करती हैं, मन उन्हें समझता है, बुद्धि निर्णय लेती है, अहंकार अनुभव को वैयक्तिक बनाता है, कर्मेंद्रियां क्रिया संपन्न करती हैं और चित्त उसे स्मृति के रूप में दर्ज करता है। गुरु ज्ञान के जिज्ञासुओं को ज्ञान प्रदान करता है जबकि सद्गुरु अपने शिष्यों में बुद्धिमत्ता का संचार करता है। उनके मार्गदर्शन से ही इन सभी अदृश्य आंतरिक जटिलताओं के बीच हमारे मन में सद्गुणों का संचार होता है।

सभी सद्गुणों से युक्त व्यक्ति एक पुष्ट फलों से युक्त फलते-फूलते वृक्ष के समान है जिसकी मज़बूत जड़ों को गुरु के ज्ञान, परिवार के सहयोग और समग्र समाज के मूल्यों से सींचा गया हो। व्यक्ति के कर्म इन आंतरिक मूल्यों की केवल अभिव्यक्ति हैं। पूर्णिमा का विशेष अवसर इन सभी तथ्यों पर आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है। यह मात्र एक खगोलीय घटना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक दर्पण है, एक सांस्कृतिक समारोह है, एक वैज्ञानिक घटना है, तथा जीवन में नवीनता लाने, चिंतन करने तथा कृतज्ञता व्यक्त करने का एक गहन प्रतीकात्मक अवसर है। इसका महत्व धर्म, ज्ञान की विभिन्न शाखाओं और सदियों तक विस्तीर्ण है तथा हमें हमारे अंत:करण में स्थित प्रकृति की लय और चक्र की याद दिलाता है। पूर्णिमा संपूर्णता और ज्ञानोदय का प्रतीक है-एक ऐसा समय है।

जबकि हम अपने स्वत्व की खोज सर्वाधिक स्पष्ट रूप में कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित करता है। योगी और संत प्राय: पूर्णिमा को गहन ध्यान, जप, उपवास और दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए एक आदर्श समय मानते हैं।

गुरु पूर्णिमा सीखने, ज्ञान अर्जन करने और कृतज्ञता व्यक्त करने का त्योहार है। सूचना की भरमार, भ्रम, तुलना और प्रतिस्पर्धा के इस युग में एक सच्चे गुरु की हमारे जीवन में उपस्थिति काफी महत्वपूर्ण है चाहे वह आध्यात्मिक गुरु हों अथवा कोई प्रशिक्षक, शिक्षा प्रदाता, माता-पिता या डिजिटल मार्गदर्शक क्यों न हों। उनकी उपस्थिति धर्म एवं धार्मिक अनुष्ठानों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी के अनिश्चितता से भरे दौर में जबकि भू-राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं, आतंकवाद, उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर युद्ध और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं युवाओं को परेशान कर रही हैं, गुरुओं और संतों की ज्ञान परंपरा का उत्सव गुरु पूर्णिमा पूरी दुनिया के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। आज के युग में लोगों द्वारा नैतिकता पर बिलकुल विचार नहीं करने एवं गलत और सही कार्यों के बीच अंतर नहीं कर पाने के कारण लोगों के सामने ढेर सारी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं तथा सामाजिक ताना-बाना बिखर रहा है। ऐसे में गुरु की उपस्थिति मात्र से ही लोगों को गलत रास्ते पर जाने से रोका जा सकता है।

आज हम जैसे-जैसे डिजिटल युग की ओर बढ़ रहे हैं, गुरु पूर्णिमा का शाश्वत संदेश हमें ज्ञान प्राप्त करने, अपने मन की शक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करने, अपने गुरुऔर मार्गदर्शक का सम्मान करने तथा दूसरों के लिए ज्ञान का स्रोत बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह समाज में मानव मूल्यों को पोषित एवं सृजित करने का एक माध्यम सिद्ध होगा।

मादक पदार्थों के खिलाफ राष्ट्रीय जन मुहिम में हिमाचल अग्रणी राज्य बनकर उभरा

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में मादक पदार्थों के खिलाफ जन मुहिम छेड़ी गई है। युवा शक्ति को नशे की बुराई से बचाने और प्रदेश में व्याप्त ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए राज्य सरकार बहुआयामी रणनीति के तहत कार्य कर रही है।

पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में सिन्थेटिक ड्रग्स के मामले सामने आए हैं। फार्मास्युटिकल हब के नज़दीक क्षेत्रों में इस तरह के मामले अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। इस खतरे से निपटने के लिए सरकार तत्परता के साथ कार्य कर रही है। फार्मास्युटिकल दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जांच एवं निगरानी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

प्रदेश सरकार ने दो महत्वपूर्ण कानून बनाकर अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत किया है। हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण एवं नियंत्रण) विधेयक, 2025 और हिमाचल प्रदेश ड्रग्स और नियंत्रित पदार्थ (रोकथाम, नशामुक्ति और पुनर्वास) विधेयक, 2025 के तहत नशे में संलिप्त लोगों के विरूद्ध कड़ी कारवाई सुनिश्चित की जा रही है। हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण एवं नियंत्रण) विधेयक में मृत्युदंड, आजीवन कारावास, भारी जुर्माना और संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े प्रावधान किए गए हैं। दूसरे विधेयक में अवैध नशीली दवाओं के व्यापार के लिए सख्त सजा सुनिश्चित की गई है। प्रदेश सरकार ने सिक्किम मॉडल से प्रेरित होकर नशामुक्ति, पुनर्वास, निवारक शिक्षा और आजीविका सहायता के लिए एक राज्य कोष बनाया गया है।

राज्य सरकार नशे के खिलाफ जीरो टोलरेंस नीति अपना रही है। तस्करों पर अंकुश लगाते हुए वर्ष 2024 में पीआईटी-एनडीपीएस के तहत निवारक निरोधक कानून को अमल में लाया गया है। इसके तहत प्रस्तुत 123 प्रस्तावों में से 41 डिटेंशन ऑर्डर जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस ने नशे की तस्करी में संलिप्त लोगों की जुड़ी 1,214 अवैध संपत्तियों की पहचान की है और अतिक्रमण के 70 मामलों में कार्रवाई की गई है तथा कुछ मामलों में संपत्तियों को जब्त किया गया है। राज्य सरकार ने नशे के कारोबार में संलिप्त 80सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी कारवाई अमल में लाई है।

इसके तहत वर्ष 2023 से 2025 के मध्य तक पुलिस विभाग ने प्रभावशाली तरीके से कार्य किया है। अढ़ाई साल की अवधि में कुल 5,004 एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए, जिनमें वर्ष 2023 में 2,147 मामले, 2024 में 1,717 और जून 2025 तक 1,140 मामले शामिल हैं।

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रदेश सरकार जन सहभागिता के साथ समाज से नशे का समूल नाश करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राज्य में नशे के विरूद्ध कानून की कड़ी अनुपालना, दोषियों के खिलाफ आर्थिक कारवाई, विधायी सुधारों, पुनर्वास जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर बहुआयामी रणनीति अपनाकर कार्य किया जा रहा है।

नशे के माध्यम से जोड़ी गई नशा कारोबारियों की संपत्ति को भी कुर्क किया जा रहा है। अढ़ाई वर्ष की अवधि के दौरान 36.95 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई। इसमें वर्ष 2023 में 4.87 करोड़ रुपये, वर्ष 2024 में 25.42 करोड़ रुपये और जून 2025 तक 6.66 करोड़ रुपये की संपत्तियां शामिल हैं। सरकार के यह कदम प्रदर्शित कर रहे हैं कि हिमाचल में नशे और इससे जुड़े हुए नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फैंका जाएगा। 7.74 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े अतिरिद्र मामलें पुष्टि के लिए भेजे गए हैं।

मार्च 2025 में, धर्मशाला, मंडी और परवाणू के तीन क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के गठन से एक बड़ा संस्थागत विस्तार मिला, यह ऊना, कुल्लू, बद्दी और सिरमौर जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। एसटीएफ के तहत तेरह पुलिस स्टेशन लाए गए हैं, जिनमें से छह पहले से ही क्रियाशील हैं जो तस्करों और अपराधियों के खिलाफ त्वरित और सटीक अभियान का संचालन सुनिश्चित कर रहे हैं।

नशे की आदत से ग्रसित लोगों को प्रभावी पुनर्वास प्रदान करने के प्रयास भी प्रगति पर है। जिला कुल्लू, ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा में पुरुषों के लिए नशामुक्ति केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जबकि कुल्लू में रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा महिलाओं के लिए एक केंद्र का संचालन किया जा रहा है। सिरमौर के कोटला बड़ोग में 100 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक नशामुक्ति केंद्र बनाया जा रहा है। सभी जिलों में ऐसे केंद्र स्थापित करने की कार्य योजना तैयार की गई है।

नशे के आदी लोगों के प्रदेश सरकार संवेदनशील रवैया अपना रही है। इन लोगों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। नशे के आदी लोगों को बेहतर चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। उनका कौशल संवर्धन कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वर्तमान में इन लोगों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आया है। बच्चों को छोटी उमर में ही नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाने के लिए स्कूली पाठयक्रम में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता पर एक अध्याय भी शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने 14 टारगेटिड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सुरक्षित सुइयों, परामर्श और एचआईवी/एसटीआई के लिए रैफरल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। यह परियोजना एचआईवी पॉजिटिव मामलों के लिए सुरक्षित सुई, परामर्श, एचआईवी/एसटीआई रेफरल सेवाएं, मौखिक दवा के विकल्प और एआरटी लिंकेज प्रदान करती हैं। नीडल सिरिंज एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत संक्रमण के प्रसार को कम करने में मदद मिल रही है।

नशे के विरूद्ध इस लड़ाई में वर्ष 2023 से जून 2025 तक, नशीले पदार्थों में 919 किलोग्राम चरस, 32.9 किलोग्राम हेरोइन, 1,632 किलोग्राम पोस्त भूसी, 89.6 किलोग्राम अफीम और 1.64 लाख से अधिक गोलियां और कैप्सूल जब्त किए गए हैं। अवैध तरीके से उगाए गए लगभग 70 लाख भांग के पौधे नष्ट किए गए हैं। नशे के तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए वार्ड वाइज मैपिंग की गई है और इसके तहत क्षेत्रों को लाल, पीले और हरे क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा रहा है।

सरकार के नशे के विरूद्ध अभियान को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। प्रदेश सरकार के इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और प्रदेश तीव्र गति से नशामुक्त हिमाचल बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। हिमाचल देश के अन्य राज्य के समक्ष एक सफल मॉडल पेश कर रहा है।

आपदा प्रभावितों के लिए वन टाइम पॉलिसी लाने पर विचार करेगी सरकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने दूसरे दिन मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों थुनाग, बगस्याड़,

देजी गांव, बाड़ा और स्यांज गांव का दौरा किया। देजी गांव में बादल फटने के कारण 11 लोग लापता हैं, जबकि बाड़ा में दो लोगों की मृत्यु हुई है। स्यांज गांव में चार व्यक्तियों की मौत हुई है जबकि पांच व्यक्ति अभी भी लापता हैं। मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों के साथ संवेदनाएं व्यक्त कीं।

पखरैर पंचायत घर में आपदा प्रभावितों ने मुख्यमंत्री को बताया कि ऐसी आपदा दो सौ साल में भी नहीं आयी। लेकिन इस बार आपदा में कई बादल फटे, बहुत सारा पानी एक साथ आया और लोग बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। मुख्यमंत्री ने राजस्व अधिकारियों को सभी तरह के नुकसान का आकलन तुरंत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन घरों में गाद भरी है या बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं अथवा जो घर अब रहने के लिए असुरक्षित हैं, उनको पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों की श्रेणी में डाला जाये ताकि प्रभावितों को अधिक से अधिक मुआवजा मिल सके। उन्होंने प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया कि उनके क्षतिग्रस्त सामान और पशुधन का मुआवजा भी सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने राजस्व अधिकारियों को फूलों की खेती करने वाले किसानों और सेब बागवानों को हुए नुकसान का आकलन करने के भी निर्देश दिए।

प्रभावितों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा मैं आपदा के इस दुःखद् समय में आपके साथ खड़ा हूं और आपको फिर से बसाने के लिए राज्य सरकार कैबिनेट से विचार करने के बाद विशेष राहत पैकेज जारी करेगी। आपदा बड़ी है, पुनर्वास में समय लगेगा लेकिन जितना भी पैसा लगे, राज्य सरकार आपकी पूरी मदद करेगी।''

बाड़ा में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को फिर बसाने के लिए वन टाइम पॉलिसी लाने पर विचार करेगी। राज्य में 68 प्रतिशत भूमि वन भूमि होने के कारण मामला केंद्र सरकार की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। थुनाग के वानिकी एवं उद्यानिकी कॉलेज की अस्थाई रूप से कक्षाएं मण्डी जिले के सुन्दरनगर में चलाई जाएंगी ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

सुक्खू ने कहा कि मंडी जिला, विशेष रुप से सराज क्षेत्र में बादल फटने के कारण काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने राहत और बचाव कार्यो के लिए सात करोड़ रुपए तुरंत प्रभाव से जारी कर दिए हैं। दो करोड़ रुपए पहले ही प्रदान कर दिए हैं और अब लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभागों को दो-दो करोड़ तथा बीडीओ को एक करोड़ रुपए और दिए जाएंगे ताकि बहाली कार्यो में और गति लाई जा सके। उन्होंने कहा कि बागबानों का भी काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार बागवानों का सेब मंडियों तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। प्रमुख सड़कें खुल चुकी हैं और अब गांव के सम्पर्क मार्गो को खोलने का काम युद्धस्तर पर जारी है।

थुनाग विश्राम गृह में आपदा प्रभावितों की सहायता कर रही एन.सी.सी. की छात्राओं ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की। मुख्यमंत्री ने उनके सेवा भाव की सराहना की। स्कूल की छात्राओं ने उन्हें स्कूल को हुए नुकसान के बारे में अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने वादा किया कि थुनाग में राज्य सरकार सीबीएसई आधारित स्कूल खोलेगी।

मुख्यमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्यो में डटे एसडीआरएफ जवानों का हौसला भी बढ़ाया और उनके काम की सराहना की। भारतीय सेना के ब्रिगेडियर यजुवेंद्र सिंह ने थुनाग में चलाये जा रहे राहत कार्यो के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी और आगे की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सेना के 26 जवान लोगों की मदद में लगे हैं। मुख्यमंत्री ने सेना के सभी जवानों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस तथा होमगार्ड के साथ-साथ सभी स्वंयसेवी संस्थाओं का मदद के लिए आभार व्यक्त किया।

बल्क ड्रग पार्क के लिए संभावित API निर्माताओं के साथ बैठक आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रस्तावित उच्च स्तरीय बैठक से पूर्व, उद्योग विभाग द्वारा हैदराबाद और मुंबई में अग्रणी API निर्माताओं, संभावित निवेशकों एवं प्रमुख फार्मा संघों के साथ महत्वपूर्ण पूर्व-तैयारी बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों का उद्देश्य ऊना जिले में विकसित किए जा रहे बल्क ड्रग पार्क को लेकर निवेशकों की रुचि जानना और उनकी अपेक्षाओं को समझना था।

इन बैठकों में Bulk Drug Manufacturers Association (BDMA), Indian Drug Manufacturers Association (IDMA), Pharmexcil एवं Telangana Association of Pharma and Chemical Industries(TAPCI) जैसे प्रतिष्ठित फार्मा संगठनों ने भागीदारी निभाई।

राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) आर. डी. नज़ीम ने किया। उनके साथ डॉ. यूनुस, निदेशक उद्योग, तिलक राज शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (उद्योग) तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर निदेशक उद्योग द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से बल्क ड्रग पार्क की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की गई तथा हिमाचल प्रदेश के फार्मा इकोसिस्टम का परिचय दिया गया। उन्होंने बताया कि राज्य में पहले से ही 650 से अधिक फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन इकाइयां कार्यरत हैं, जिनमें Alkem Labs, SunPharma, Abbott, Dr- Reddy's जैसी अग्रणी कंपनियां शामिल हैं, जो राज्य के मजबूत फार्मा आधार को दर्शाता है।

उन्होंने आगे बताया कि यह प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क प्रतिवर्ष रू38,000 करोड़ से अधिक की API मांग को पूरा करेगा, न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे पांच पड़ोसी राज्यों में भी। यह पार्क हरोली तहसील में 1,405 एकड़ में फैला होगा, जो पंजाब सीमा के समीप है और उत्कृष्ट कनेक्टिविटी तथा अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। पार्क में CETP (Zero Liquid Discharge सहित), स्टीम एवं पावर जनरेशन, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, गोदाम, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी प्रमुख साझा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इन बैठकों में Dr.Reddy's, Alkem Labs, Sun Pharma, Abbott, Aurobindo Pharma, Covalent Labs,Torrent Pharma, Mankind Pharma, Mahima Life Sciences जैसी अग्रणी फार्मा कंपनियों सहित Thermax एवं Balaji Infrastructure जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञों सहित 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने आगामी पार्क में निर्माण इकाइयां स्थापित करने में गहरी रुचि दिखाई।

बैठक के दौरान संभावित निवेशकों ने CETP एवं स्टीम जनरेशन शुल्क जैसे परिचालन पहलुओं पर प्रश्न उठाए और शुल्क निर्धारण में पारदर्शिता तथा स्थायित्व की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को प्रतिस्पर्धी लागत बनाए रखने हेतु उपयोगिता शुल्कों में अनावश्यक वृद्धि से बचाव के लिए स्पष्ट और स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि उनकी चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और उपयोगिताओं के प्रबंधन हेतु एक मजबूत, किफायती एवं विश्वसनीय ढांचा विकसित किया जा रहा है।

यह बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश को उच्च गुणवत्ता वाली API एवं फार्मास्युटिकल विनिर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इसके अतिरिक्त, उद्योग विभाग द्वारा सीमेंट उद्योग के प्रमुख खिलाड़ियों के साथ भी एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा SBI CAPS की सलाहकार भूमिका में दो चूना पत्थर खनिज ब्लॉकों की नीलामी हेतु शीघ्र जारी होने वाले NIT (निविदा सूचना) के संदर्भ में चर्चा की गई। यह पहल राज्य की समृद्ध चूना पत्थर खनिज संपदा के दोहन हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी को आमंत्रित करेगी और ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड सीमेंट परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय रोजगार सृजन एवं औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेगी। इस बैठक में Ultratech, Adani, Nuvoco Vista जैसी प्रमुख सीमेंट कंपनियों ने भाग लिया और निविदा में रुचि दर्शाई।

सराज में युद्ध स्तर पर किया जा रहा पेयजल योजनाओं की बहाली का कार्य: उप-मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री एवं जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा के कारण जल शक्ति विभाग की 241 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं और इनकी बहाली का कार्य विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अब तक 150 योजनाओं को आंशिक रूप से बहाल किया गया है जबकि शेष योजनाओं को शीघ्र बहाल करने के लिए विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी दिन-रात दुर्गम परिस्थितियों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं की मरम्मत के लिए अनुकूल मौसम के बावजूद दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ एवं निर्बाध पेयजल सुनिश्चित करवाने के दृष्टिगत कार्य किया जा रहा है।

अग्निहोत्री ने कहा कि वह स्वयं राहत एवं बचाव कार्यो तथा क्षतिग्रस्त योजनाओं की बहाली के कार्यो की नियमित समीक्षा कर रहे हैं तथा ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लोगों को पेयजल सहित अन्य आवश्यक सामग्री सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सुंदरनगर में लगेंगी औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय थुनाग की कक्षाएं:जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि 30 जून की रात को आयी आपदा से बने हालातों के मद्देनजर औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय थुनाग में विद्यार्थियों की कक्षाएं जारी रखना संभव नहीं है। इस महाविद्यालय में लगभग 300 छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से इस संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया है। विद्यार्थियों और अभिभावकों ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कर आपबीती सुनाई है।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने गहन विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय थुनाग की कक्षाएं अब सुंदरनगर में लगाई जाएंगी। यह वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है क्योंकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि है।

मंत्री ने कहा कि औद्यानिकी एवं वानिकी विवि नौणी को सुंदरनगर में लोकेशन की पहचान कर तुरंत प्रभाव से कक्षाएं शरू करने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं। आपदा के कारण बच्चों की पढ़ाई को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए 14 जुलाई तक छुट्टियां घोषित की गई हैं।

जगत सिंह नेगी ने कहा आपदा में थुनाग महाविद्यालय के विद्यार्थी बाल-बाल बचे। पूर्व सरकार ने अधोसंरचना तैयार किए बिना थुनाग में कक्षाएं शुरू कर दीं और ज्यादातर विद्यार्थी पी.जी में रह रहे थे। थुनाग महाविद्यालय में नए सत्र के लिए 100 विद्यार्थियों की दाखिला प्रक्रिया भी जारी है। उनकी पढ़ाई में व्यवधान न हो, इसलिए ये कक्षाएं भी सुंदरनगर में लगाई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2023 में 10 हजार करोड़ रुपये आपदा उपरांत आवश्यकता आकलन किया गया। केंद्र ने दो साल बाद सिर्फ 2006 करोड़ रुपये की राशि जारी की है जिसमें 25 फीसदी हिस्सा प्रदेश सरकार को जमा करना है। उन्होंने कहा कि 2024 में भी मानसून में भारी क्षति हुई है लेकिन केंद्र ने अभी तक कोई सहायता नहीं की है।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल से हैं और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी। उन्हें और चारों भाजपा सांसदों को प्रदेश के हितों के लिए केंद्र सरकार के समक्ष आवाज उठानी चाहिए।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ दिल्ली जाने के लिए सहमत हो गए हैं। केंद्र सरकार के समक्ष वे प्रदेश के हितों के लिए अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे जिससे आपदा प्रभावितों के पुर्नवास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने 2023 में ही यह हामी भरी होती तो शायद प्रदेश को पूरी राहत राशि मिलती।

मंत्री ने कहा कि मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत पर तंज कसते हुए कहा कि नदी-नालों से गुजरकर आपदा प्रभावित परिवारों तक पहुंचना, उनका दुःख दर्द बांटना और जनसेवा करना अभिनेत्री के बस का काम नहीं है वे सिर्फ बॉलीवुड में ही काम कर सकती हैं जहां मंच सजा होता है, मेकअप मैन है, डायलॉग राइटर ने डायलॉग तक लिख कर दिए होते हैं।

शिमला में जल सेवाओं के लिए 24X7 हेल्पलाइन नंबर शुरू अब एक कॉल पर मिलेगी मदद

शिमला/शैल। शिमला जल प्रबंधन निगम और सूएज़ ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक और महत्वपूर्ण पहल की है। शहर में जल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों और जानकारी के लिए अब एक समर्पित 24X7 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। यह नंबर है 8767198000। इस सेवा के शुरू होने से शिमला के नागरिकों को अब किसी भी समय जल सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करने की सुविधा मिलेगी।

इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से उपभोक्ता अब जल आपूर्ति से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यह सेवा चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगी जिससे आम जनता को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

एसजेपीएनएल और सूएज़ द्वारा दी जा रही यह सुविधा जल प्रबंधन प्रणाली को न केवल अधिक जवाबदेह बनाएगी, बल्कि उपभोक्ताओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी। इस पहल के पीछे मकसद है कि नागरिकों को समय पर सही जानकारी और त्वरित समाधान मिले, जिससे न केवल उनका समय बचे बल्कि व्यवस्था पर भी भरोसा बढ़े। संस्थान की ओर से बताया गया है कि कॉल सेंटर में प्रशिक्षित प्रतिनिधि हर कॉल को गंभीरता से सुनेंगे और समस्याओं को रिकॉर्ड कर संबंधित तकनीकी टीमों तक पहुंचाएंगे। इसके बाद त्वरित कारवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हवाई सम्पर्क विस्तार और शिमला व धर्मशाला को नियमित हवाई सेवाओं का आग्रह किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से भेंट कर हिमाचल

प्रदेश में हवाई सम्पर्क को सुदृढ़ करने को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

उन्होंने दिल्ली – शिमला – धर्मशाला और धर्मशाला – शिमला – दिल्ली हवाई उड़ानों का संचालन नियमित रूप से करने का आग्रह किया जो वर्तमान में केवल तीन दिन ही संचालित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि नियमित उड़ाने नहीं होने से पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने धर्मशाला नाइट लेडिंग की सुविधा शुरू करवाने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने नायडू को कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की स्थिति की जानकारी दी और भूमि अधिग्रहण की अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए विशेष सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के साथ भी इस विषय पर चर्चा कर नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सहायता का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे के निर्माण से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।

सुक्खू ने प्रदेश में हवाई सम्पर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चार नए हैलीपोर्ट के निर्माण का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने शिमला हवाई अड्डे के विस्तार पर भी चर्चा की और वहां की वॉच ऑवर समय सीमा को दोपहर एक बजे से आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर शिमला में डॉर्नियर प्रकार के विमानों के संचालन का प्रस्ताव भी दिया। उन्होंने शिमला के लिए अतिरिक्त एयरलाइन ऑपरेटर की सेवाएं प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

मुख्यमंत्री ने जापान में कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को शुभकानाएं दीं

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जापान के ओसाका में 15 से 23 जुलाई, 2025 तक आयोजित होने वाली

शिटोकाई गोजू – रियू कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 20 सदस्यीय भारतीय दल को अपने अधिकारिक आवास ओक ओवर से रवाना किया। भारतीय दल को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना समस्त देशवासियों और खिलाड़ियों के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों के परिश्रम की सराहना करते हुए उनके बेहतर प्रदर्शन और जीत की कामना की।

कराटे प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले 20 सदस्यीय दल में 11 खिलाड़ी जिला शिमला के बाघी स्थित रूट्स कंट्री स्कूल से हैं तथा शेष खिलाड़ी हिमाचल सहित देशभर के विभिन्न क्षेत्रों से हैं। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम पांच वर्षों के अंतराल के बाद भाग ले रही है। खिलाड़ियों सहित टीम के हेड कोच सैन्सी अनिल कुमार जिश्टा और सहायक कोच सैन्सी हरि तमंग भी जापान जा रहे हैं। इस अवसर पर रूट्स कंट्री स्कूल के संस्थापक सुनील रोहटा भी उपस्थित थे।

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 13 हजार से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच, साढ़े पांच हजार को बांटी आवश्यक दवाइयां: डॉ. शांडिल

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं

अधिकारिता व सैनिक कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने मंडी जिला के सराज में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर यहां हुए नुकसान तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने आपदा प्रभावितों से भेंट की और इस संकट की घड़ी में सभी प्रभावितों के साथ एकजुट खड़े रहकर प्रदेश सरकार की ओर से हरसंभव मदद की प्रतिबद्धता जताई।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सराज क्षेत्र को सात करोड़ रुपए तुरंत प्रभाव से जारी किए गए हैं। आपदा में बेघर हुए परिवारों को गृह निर्माण के लिए सात लाख रुपए तथा छः माह तक मकान किराए के रूप में पांच हजार रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग को भी बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। आपदा के उपरांत दुर्गम क्षेत्रों तक बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभाग निरंतर प्रयासरत है। अभी तक सराज के आपदा प्रभावित थुनाग व जंजैहली क्षेत्रों में 13,353 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त 5527 रोगियों को घर – गांव में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि आपातकालीन एवं गंभीर बीमारी से ग्रस्त रोगियों के लिए प्रचुर मात्रा में दवाइयों का भंडारण किया गया है। चिकित्सा अधिकारी जंजैहली, बगस्याड व करसोग के लिए तीन आपातकालीन चिकित्सा किट, 62 बॉक्स दवाइयों व इंजेक्शन के भेजे गए हैं।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को क्लोरीन की गोलियां वितरित करने के साथ ही इनके समुचित उपयोग पर भी जानकारी प्रदान की जा रही है। ओआरएस के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं तथा जलजनित रोगों से बचाव के लिए घर – घर जाकर जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से बगस्याड क्षेत्र में जन्म प्रतिक्षा गृह स्थापित किया गया है जो कि प्रसव पूर्व मातृत्व संबंधी मामलों तथा सुरक्षित प्रसव में उपयोगी भूमिका निभा रहा है। सड़क सम्पर्क से वंचित क्षेत्रों में घर – घर जाकर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। जरूरतमंद रोगियों एवं गर्भवती महिलाओं को मेडिकल कॉलेज नेरचौक तथा क्षेत्रीय अस्पताल मंडी तक सुरक्षित पहुंचाया गया है।

उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पेयजल सहित सभी आवश्यक सेवाएं बहाल करने के लिए भी युद्ध स्तर पर कार्य जारी है।

मुख्यमंत्री ने बांस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के निदेशक मंडल की 215वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निगम की कार्य प्रणाली में आधुनिक तकनीक का समावेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम के सभी टिंबर गोदामों में बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने ऊना जिला के गगरेट में बांस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा ताकि ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर तथा हमीरपुर जिला के किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान किए जा सकें। उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए वन निगम में राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली (ट्रांजिट पास) को एकी त करने के भी निर्देश दिए।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि एचपीएसएफडीसी ने वर्ष 2024 – 25 में लकड़ी, राल और तारपीन तेल की बिक्री से कुल 289.91 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जिससे वर्ष 2024 – 25 में 14.93 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है। वर्ष 2023 – 24 में निगम द्वारा कुल 267 करोड़ रुपये की बिक्री की गई थी और 7.88 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त हुआ था। इसके अलावा सेल्वीकल्चर कटान से निगम को 41.30 करोड़ रुपये की रॉयल्टी प्राप्त हुई है।

नादौन से सराज पहुंची आपदा राहत सामग्री, मुख्यमंत्री ने जताया आभार

शिमला/शैल। मण्डी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राहत कार्यों में जहां

प्रशासन जुटा हुआ है, वहीं सामाजिक संस्थाएं और आमजन भी बड़ी संख्या में लोगों को राहत सामग्री प्रदान करने के लिए आगे आ रहे हैं।

इसी क्रम में, हमीरपुर जिला की नादौन विधानसभा के बड़ा जोन से भी राहत सामग्री भेजी गई है। राहत सामग्री मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू को थुनाग में औपचारिक रूप से सौंपी गई। राहत सामग्री में 5 बोरी आटा, 11 बोरी चावल, एक क्विंटल चीनी, 60 किलो चने की दाल, 60 किलो माह, 45 लीटर तेल, 50 किलो आलू, 10 बाल्टियां, 10 मग, 90 जोड़ी जूते – चप्पल, 3700 प्लेटें व गिलास, प्रेशर कुक्र, बच्चों के दूध की बोतलें और स्नान व कपड़े धोने का साबुन शामिल है।

एसबीआई के सेवानिवृत्त प्रबंधक सुदर्शन जरियाल, पूर्व उप – प्रधान राजेश कुमार, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सदस्य कुलदीप कुमार, जीत सिंह, निखिल कुमार, अतुल पटियाल और बलवीर सिंह ने मुख्यमंत्री के सराज दौरे के दौरान मुख्यमंत्री को यह सामग्री सौंपी।

मुख्यमंत्री ने इस पुण्य कार्य के लिए सभी दानी सज्जनों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह राहत सामग्री उपायुक्त मंडी के माध्यम से आपदा प्रभावित परिवारों को वितरित की जाएगी।

हिमालयन ट्राइब फाउंडेशन धार्मिक स्थलों में चलायेगा सफाई अभियान

शिमला/शैल। हिमालयन ट्राइब फाउंडेशन प्रदेश के पहाड़ों को प्लास्टिक का पहाड़ बनने से रोकगा।

खासकर धार्मिक यात्राओं के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा फैलाए जा रहे प्लास्टिक के कचरे को पनपने नहीं देगा। हिमाचल प्रदेश में हिमालयन ट्राइब फाउंडेशन एक मात्र एनजीओ है जो हर वर्ष धार्मिक यात्राओं के दौरान सफाई अभियान चलाकर सैंकडों कट्टे में प्लास्टिक के कचरे रि – साइकल के लिए लाया गया। जो अपने आप में मील का पत्थर साबित हुआ। हिमालयन ट्राइब फाउंडेशन ने इस बार भी 19 से 23 जुलाई तक श्रीखंड यात्रा मार्ग पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस बात की जानकारी हिमालयन ट्राइब फाउंडेशन के संस्थापक आरपी नेगी युल्लाम ने दी। उन्होंने कहा कि हाल ही में किन्नौर के युला कंडा, भावा, रामपुर समेत अन्य क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया। गौरतलब है कि पिछले वर्ष हिमालयन ट्राइब फाउंडेशन ने पिछले साल श्रीखंड महादेव यात्रा मार्ग पर सफाई अभियान चलाया और यात्रियों द्वारा छोड़े गए प्लास्टिक कचरे को हटाया। आरपी नेगी युल्लाम ने कहा कि इस बार श्रीखंड यात्रा के दौरान पार्वति कुंड को स्वच्छ बनाने और इस क्षेत्र में 500 कट्टे प्लास्टिक कचरे एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कूड़े के बढ़ते ढेर के साथ, स्थिति हर साल बदतर होती जा रही है। ऐसे में हमारा लक्ष्य सिर्फ़ क्षेत्र को साफ़ करना नहीं है, बल्कि इन प्रयासों के माध्यम से यह संदेश भी देना है कि मानव बस्तियों से दूर, ऐसे पवित्र और मनोरम स्थानों पर पर्यावरण की रक्षा करना ज़रूरी है। इसके साथ – साथ हिमालय की गोद में से धार्मिक स्थलों को कूड़ा मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि चाहे धार्मिक स्थल हों या पर्यटन स्थल, पर्यटकों को प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल सुनिश्चित करना चाहिए। आरपी नेगी युल्लाम ने प्रदेश की जनता से इस सफाई अभियान में जुड़ने की अपील भी की है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

केंद्र सरकार हर प्रभावित व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध:नड्डा

शिमला/शैल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और बादल फटने व भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति का निरीक्षण किया। नड्डा ने मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र स्थित सैंज पंगलियूर बागा गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से बात की। उन्होंने थुनाग में भी आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और लोगों से बात की साथ ही उन्होंने करसोग और धर्मपुर में हुए नुकसान पर भी चिंता व्यक्त की। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी मौजूद थे।

जेपी नड्डा ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राहत कार्यो में कोई ढिलाई न बरती जाये और हर प्रभावित व्यक्ति तक सरकार की सहायता शीघ्र पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ पूर्ण समन्वय में कार्य कर रही है और आवश्यक संसाधन समय पर मुहैया कराए जा रहे हैं। तत्पश्चात उन्होंने मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र स्थित सैंज पंगलियूर बागा गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने आपदा से प्रभावित परिवारों से भेंट की। इस दौरान वह पुष्प राज और तिलक राज ने मिले जिन्होंने इस त्रासदी में अपने माता पिता को खो दिया।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना देते हुए कहा कि केंद्र सरकार उनके पुनर्वास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। इसके बाद नड्डा ने मंडी जिले के ही थुनाग गांव का दौरा किया, जहां भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने वहां स्थानीय लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनीं और राहत सामग्री वितरण की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने, अस्थाई आश्रय देने और भोजन व दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन युद्धस्तर पर कार्य कर रहा है। उन्होंने राहत शिविरों में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया और इस बाबत अधिकारियों को निर्देश दिए।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राहत कार्यो के बाद जिन क्षेत्रों में संपर्क मार्ग टूट गए हैं, उनकी शीघ्र मरम्मत कर पुन: यातायात सुचारू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है और ऐसे समय में सरकार और समाज को मिलकर एकजुटता दिखानी चाहिए।

जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि अगर राहत की बात करें तो भारत सरकार इस कार्य में हमेशा तत्पर है, आर्थिक मदद की दृष्टि से भारत सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ पहले भी खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी।

2023 को याद दिलाते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उस समय मंडी एवं कुल्लू में त्रासदी आई थी और मैं तीन बार हिमाचल प्रदेश आया था, मुझे याद है कि उस समय 3146 करोड़ की राहत हमने केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश को पहुंचाई थी। अभी भी पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2006 करोड़ एनडीआरएफ के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए जारी किया है, अगर इसका जोड़ करें तो कुल 5152 करोड़ बनता है। आर्थिक दृष्टि से बात करें तो मदद के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक घर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3000 करोड़ से अधिक सड़के केंद्र सरकार ने हिमाचल को दी है।

नड्डा ने कहा कि हिमाचल की जनता आश्वस्त रहे कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को कभी छोड़ेगी नहीं हमेशा साथ खड़ी रहेगी और मैं केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते यह जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि भारत सरकार हिमाचल के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर प्रभावित व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सामान्य जनजीवन जल्द बहाल हो सके।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जब भी हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आयी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने वहां का दौरा किया है, लोगों से बात की है तथा केंद्र से इस आपदा से उबरने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है।

आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्वास हमारी प्राथमिकता:अनुराग सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह प्रभावित मंडी ज़िले के सराज विधानसभा के बगस्याड़, थुनाग व सराज बाज़ार में आपदाग्रस्त परिवारों को मिलकर ढांढस बंधा कर समस्याओं की सुनवाई की व राहत सामग्री का वितरण किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर राहत व पुनर्वास कार्यो को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने निजी प्रयासों से सराज विधानसभा में 1000 स्कूल बैग, 2000 कॉपी, 2000 पेंसिल, 1000 बॉक्स, 1000 पेन, 1000 शार्पनर, 5000 बिस्किट पैकेट, 5000 प्रोटीन बॉक्स 1000 क्लिप बोर्ड स्कूली बच्चों को बांटने का काम किया है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा हिमाचल में प्राकृतिक आपदा का रूप बहुत भयावह है ख़ासकर मंडी क्षेत्र में आपदा ने विकराल क़हर ढाया है। कई लोगों ने पाई-पाई जोड़कर जो घर बनाये थे वो बारिश में बह जाने से आज सार्वजनिक जगहों जगहों पर रहने के लिए मजबूर हैं। त्रासदी से हज़ारों करोड़ का नुक़सान तो हुआ ही साथ ही जान-माल का नुक़सान अत्यंत भयावह है। सराज में पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्थानीय विधायक होने के नाते गांव-गांव जाकर हालात का जायज़ा लिया व पीड़ितों की मदद करने का सराहनीय कार्य किया। मंडी में प्रदेश भर से मदद पहुंच रही है और हमने भी सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से 2000 से ज्यादा लोगों को जांच, उपचार, दवा व सेनेट्री पैड के वितरण का काम किया है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्वास हमारी प्राथमिकता है और साथ मिलकर जल्द ही हम हालत को सामान्य करने में कामयाब होंगे।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा आपदा की इस घड़ी में भाजपा परिवार पीड़ितों की हरसंभव मदद करने का प्रयास कर रहा है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा इस दुख की घड़ी में भाजपा ने लगातार प्रयास किये हैं कि लोगों की मदद के लिये जमीन पर सक्रिय रहें। राहत सामग्री के रूप में राशन, बर्तन, दवाईयां हों, लोगों का उपचार हो इसमें मदद की है और आगे भी करेंगे। जहां तक केंद्र से मदद की बात है तो पहले भी सेना, एनडीआरएफ की मदद मिली है, केंद्र ने मदद की है। केंद्र की तरफ़ से कोई कमी कभी नहीं रही और न ही आगे रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में मदद के लिए अपनी सांसद निधि से कुछ पैसे दे रहा हूं और कुछ पैसे मनरेगा से लगवाकर, एसडीएम और तहसीलदार से बात हुई, इसका काम स्थानीय पंचायतों के प्रधान करवायेंगे ताकि घरों को क्षति न हो और पानी डायवर्ट किया जा सके। आगे भी जहां क्रेटवाल लग सकती है उसका सर्वे करने के बाद सरकार के सामने मांग उठायेंगे और भविष्य में जहां से पानी आता है उसे डायवर्ट कर जिससे घरों की तरफ़ पानी न आकर नालों में जाये, उस दिशा में जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उस पर चर्चा की जा रही है।